



मित्रता शुद्धतम प्रेम है। ये प्रेम का सर्वोच्च रूप है, जहां कुछ भी नहीं मांगा जाता, कोई शर्त नहीं होती, जहां बस देने में आनंद

आता है।

-ओशो

मूल्य ₹ 3/-

जिद...सच की

www.4pm.co.in www.facebook.com/4pmnewsnetwork @Editor_SanjayS YouTube 4pm NEWS NETWORK

वर्ष: 12 अंक 111 पृष्ठ: 8 लखनऊ, बुधवार 27 मई, 2026

करो या मरो के मैच में उतरेंगे हैदराबाद... 7 फाल्ता में हार टीएमसी की सियासत... 3 राजनीतिक लाभ के लिए पुलिस का... 2

राहुल गांधी ने भिजवा दिया सिद्धारमैया को त्यागपत्र संदेश

सीएम को मिलेगा सम्मानजनक एगिजट पैकेज

- » बेटा डिप्टी सीएम और समर्थक विधायकों को मंत्रीपद
- » दिल्ली दरबार में झुके सिद्धा, बेंगलुरु में बजेगा डीके राज का बिगुल
- » इस्तीफे की पटकथा तैयार?
- » राज्यपाल भवन तक पहुंच चुका सत्ता परिवर्तन का संदेश

4पीएम न्यूज नेटवर्क

बेंगलुरु। कर्नाटक की सत्ता में आखिर वह विस्फोट हो गया जिसकी आहट पिछले कई महीनों से सुनाई दे रही थी। कांग्रेस के भीतर चल रहा ढाई साल बनाम पूरा कार्यकाल का युद्ध अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री सिद्धारमैया कल राज्यपाल से मुलाकात कर अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं और इसके साथ ही डीके शिवकुमार के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता लगभग साफ माना जा रहा है।

सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश यह निकल रहा है कि आखिरकार सिद्धारमैया ने राहुल गांधी और कांग्रेस हाईकमान के सामने सरेण्डर कर दिया है। दिल्ली में हुई हाई वोल्टेज बैठकों के बाद अचानक घटनाक्रम जिस तेजी से बदला उसने साफ कर दिया कि कांग्रेस अब कर्नाटक में सत्ता संघर्ष को और लंबा खींचने के मूड में नहीं है। पार्टी को डर था कि अगर अंदरूनी लड़ाई खुलकर सामने आ गई तो दक्षिण भारत में उसका सबसे मजबूत किला दरक सकता है। यही वजह है कि राहुल गांधी ने सीधे हस्तक्षेप किया और सत्ता परिवर्तन का फॉर्मूला आगे बढ़ाया गया। अब चर्चा यह है कि सिद्धारमैया को सम्मानजनक एगिजट पैकेज दिया गया है, राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी भूमिका बेटे यतींद्र के लिए बड़ी जिम्मेदारी और समर्थकों को मंत्रालयों में हिस्सेदारी।

झुक गये सिद्धारमैया

लेकिन असली कहानी सिर्फ इस्तीफे की नहीं, बल्कि उस राजनीतिक दबाव की है जिसने सिद्धारमैया जैसे मजबूत नेता को झुकने पर मजबूर कर दिया। चुनाव जीतने के बाद सिद्धारमैया खेमा लगातार दावा करता रहा कि सरकार उनकी लोकप्रियता के दम पर बनी। पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और ग्रामीण वोट बैंक पर उनकी पकड़ कांग्रेस की ताकत मानी जाती रही। ऐसे में उनका हटना सिर्फ नेतृत्व परिवर्तन नहीं बल्कि कांग्रेस के भीतर शक्ति संतुलन बदलने का संकेत भी माना जा रहा है। उधर डीके शिवकुमार के समर्थकों में माहौल पूरी तरह जशन वाला हो चुका है। बेंगलुरु में पोस्टर लगने शुरू हो गए हैं सोशल मीडिया पर नेक्स्ट सीएम डीके ट्रेंड हो रहा है और पार्टी के भीतर यह संदेश देने की कोशिश हो रही है कि आखिरकार संगठन के असली रणनीतिकार को उसका इनाम मिल गया। शिवकुमार खेमा इसे कमिंटेंट की जीत बता रहा है। दावा किया जा रहा है कि सत्ता साझा करने का वादा पहले दिन से था और अब हाईकमान सिर्फ उसी समझौते को लागू कर रहा है।



क्या चुप बैठेगा सिद्धारमैया खेमा

लेकिन राजनीति में हर सत्ता परिवर्तन अपने पीछे बारूद भी छोड़ता है। सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि क्या सिद्धारमैया का खेमा चुप बैठेगा? क्या मंत्री और विधायक खुलकर नाराजगी दिखाएंगे? क्या कांग्रेस के भीतर सॉफ्ट रेबेलियन शुरू होगा? और सबसे अहम क्या बीजेपी इस पूरे घटनाक्रम को ऑपरेशन लोटस के मौके में बदलने की कोशिश करेगी? फिलहाल कर्नाटक में सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं बदल रहा बल्कि कांग्रेस के भीतर ताकत का पूरा नक्शा बदलता दिखाई दे रहा है। और इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात साफ कर दी है कि दिल्ली दरबार में आखिरी मुहर राहुल गांधी की ही चलती है।

पूरे संकट को कंट्रोल्ड ट्रान्जिशन बनाना चाहते है राहुल



राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राहुल गांधी इस पूरे संकट को कंट्रोल्ड ट्रान्जिशन बनाना चाहते हैं। वह नहीं चाहते कि पंजाब या राजस्थान जैसी स्थिति दोहराई जाए जहां अंदरूनी संघर्ष ने पार्टी को कमजोर कर दिया था। लेकिन कर्नाटक का मामला ज्यादा संवेदनशील है क्योंकि दक्षिण भारत में कांग्रेस के पास यही सबसे बड़ा राज्य है। अगर यहाँ अस्थिरता बढ़ती है तो उसका असर राष्ट्रीय

राजनीति पर भी पड़ेगा। कर्नाटक में फिलहाल जनता से ज्यादा नेता बेचैन हैं। सत्ता के गलियारों में हर कोई एक-दूसरे की बाँड़ी लैंग्वेज पढ़ रहा है। कोई दिल्ली के संकेत देख रहा है कोई पोस्टर की भाषा समझ रहा है तो कोई सुबह के नाश्ते में परोसी जाने वाली मुस्कान के पीछे छिपे राजनीतिक दर्द को। लेकिन एक बात तय है कि ब्रेकफास्ट सिर्फ कॉफी और इडली का कार्यक्रम नहीं यह तय करेगा कि कांग्रेस एकजुट पार्टी की तस्वीर पेश करेगी या फिर कर्नाटक से राष्ट्रीय स्तर तक फैलने वाला नया सत्ता संग्राम शुरू हो जाएगा।

कांग्रेस की राजनीति थाली में बहुत कुछ

सबसे दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस नेतृत्व सिर्फ सीएम बदलने की मशवकत नहीं कर रहा बल्कि बगावत रोकने का गणित भी तैयार कर रहा है। सिद्धारमैया को राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी भूमिका उनके बेटे यतींद्र को डिप्टी सीएम पद, तीन-चार नए उपमुख्यमंत्री जातीय संतुलन मंत्रालयों की नई डील यानी कुर्सी बचाने के लिए



पूरी राजनीतिक थाली सजाई जा रही है। लेकिन सवाल वही है क्या

इतने रायते के बाद भी पार्टी एकजुट दिख पाएगी? और यहीं से कहानी में सबसे विस्फोटक एंगल एंट्री मारता है अगर सिद्धारमैया हटते हैं और उनके समर्थक खुलकर नाराज हो जाते हैं तो क्या कांग्रेस के भीतर सॉफ्ट विद्रोह शुरू हो सकता है? क्या बीजेपी इसी मौके का इंतजार कर रही है? क्या कांग्रेस का दक्षिणी किला

अंदरूनी लड़ाई में ही कमजोर हो जाएगा? या फिर राहुल गांधी आखिरी वक्त पर ऐसा फॉर्मूला निकालेंगे कि दोनों नेताओं को लगे कि जीत उसी की हुई है। कर्नाटक में फिलहाल राजनीति नहीं चल रही बल्कि सत्ता का हाई-वोल्टेज रियलिटी शो चल रहा है। जहाँ एक तरफ कॉफी के कप हैं दूसरी तरफ कुर्सी का करंट।

राजनीतिक लाभ के लिए पुलिस का दुरुपयोग कर रही प्रदेश की योगी सरकार : अखिलेश यादव

» सपा प्रमुख बोले- राज्य में फर्जी मुठभेड़ों के जरिए आपराधिक तंत्र स्थापित किया जा रहा है

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का भाजपा और योगी सरकार पर हमला जारी है। यूपी के पूर्व सीएम ने सरकार पर फर्जी मुठभेड़ों के जरिए एक आपराधिक तंत्र स्थापित करने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि सरकार राजनीतिक लाभ के लिए पुलिस का दुरुपयोग करती है और गोरखपुर मुठभेड़ मामले की तरह दोषी पाए जाने पर उनसे पल्ला झाड़ लेती है।

समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने 26 मई को योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार की आलोचना करते हुए उस पर फर्जी मुठभेड़ों के माध्यम से एक आपराधिक तंत्र स्थापित करने और पुलिस कर्मियों का राजनीतिक उद्देश्यों के लिए दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। यादव ने दावा किया कि सरकार मुठभेड़ों में तैनात पुलिसकर्मियों को बाद में छोड़ देती है। गोरखपुर फर्जी मुठभेड़ मामले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कई पुलिसकर्मियों को जेल में डाल दिया गया है जबकि सरकार ने उनसे पल्ला झाड़ लिया है। यादव ने कहा कि फर्जी मुठभेड़ों के जरिए पूरा आपराधिक तंत्र खड़ा हो गया है। कुछ



दोषी पुलिसकर्मियों को सजा देने के बाद उनसे मुंह मोड़ लेती है सरकार

भाजपा सरकार फर्जी मुठभेड़ों में दोषी पुलिसकर्मियों को सजा देने के बाद उनसे मुंह मोड़ लेती है। सरकार पुलिसकर्मियों को इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर रही है। पुलिसकर्मियों को यह समझना चाहिए कि भविष्य में उनके अपने परिवार वाले भी उन्हें हत्या समझेंगे। यादव ने आगे कहा कि फर्जी मुठभेड़ों में शामिल पुलिस अधिकारियों को आजीवन परिणाम भुगताने होंगे। उन्होंने इस प्रथा की निंदा करते हुए इसे अलोकतांत्रिक बताया और सरकार पर इसके जरिए मनोवैज्ञानिक दबाव डालने का आरोप लगाया। उन्होंने आगे कहा कि फर्जी मुठभेड़ों में हत्या करने वाले पुलिसकर्मियों हर दिन धीमी मौत मरते हैं। कई अधिकारियों ने मुठभेड़ों के डर का फायदा उठाकर महिलाओं के खिलाफ अपराध किए हैं। फर्जी मुठभेड़ों के डर से निवेश नहीं आता, भाजपा को भी अपने ही लोगों को नुकसान होता है। जाति आधारित फर्जी मुठभेड़ें हो रही हैं। सपा प्रमुख और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में सपा की सरकार बनने पर भाजपा की केंद्र सरकार गिर जाएगी। उनसे कांग्रेस नेता राहुल गांधी के एक साल के भीतर केंद्र सरकार गिर जाने संबंधी बयान पर सवाल पूछा गया था।

कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर पर भी साधा निशाना

इस अवसर पर अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह ने उत्तर प्रदेश में फर्जी एनकाउंटर पर मानवाधिकार रिपोर्ट साझा की। गाजीपुर के सपा नेता रमाशंकर राजभर ने राजभर समाज के युवाओं के फर्जी एनकाउंटर के लिए भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराया। साथ ही कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर पर भी निशाना साधा। हत्यारों के वीरेंद्र कुशवाहा ने अपनी बहन शिल्पी कुशवाहा की हत्या और परिवार के उत्पीड़न का मुद्दा उठाया।

वकील फर्जी मुठभेड़ों के बारे में बढ़ा-चढ़ाकर बातें करते हैं और मनगढ़ंत कहानियां सुनाते हैं। जब पुलिसकर्मियों फर्जी मुठभेड़ों में फंस जाते हैं, तो सरकार उनसे मुंह मोड़ लेती है। आज गोरखपुर फर्जी मुठभेड़ मामले के कारण कई पुलिसकर्मियों जेल में हैं।

हत्या को हिंसा के रूप में पेश किया जा रहा

यादव ने समझाया कि मुठभेड़ को आम तौर पर झड़प कहा जाता है। इसमें हिंसक और आपराधिक गतिविधियों की कोई जगह नहीं है। फर्जी मुठभेड़ों के जरिए एक 'मानसिक सॉफ्टवेयर' सेट किया जाता है, लेकिन उसे अपडेट नहीं किया जाता। लोगों में हिंसा भड़काई जा रही है। हत्या को हिंसा के रूप में पेश किया जा रहा है। फर्जी मुठभेड़ें गलत हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ हैं। सरकार फर्जी मुठभेड़ों के जरिए अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रही है। यह कई जगहों पर देखा जा रहा है।

एनकाउंटर में मारे गए 85 फीसदी लोग पीडीए समाज से

साथ ही अखिलेश ने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार के 10 साल में पीडीए (पिछड़ों, दलितों व अल्पसंख्यकों) पर अत्याचार की इतना हो गई है। सरकार ने बड़े पैमाने पर फर्जी एनकाउंटर कराए हैं। इनमें मारे गए 85 फीसदी लोग पीडीए समाज से हैं।

महंगाई, बिजली संकट, पेपर लीक व चोरी समेत कई मुद्दों को लेकर सपा का प्रदर्शन



सुलतानपुर। समाजवादी पार्टी ने बढ़ती महंगाई, भीषण बिजली संकट और नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। मंगलवार को सुलतानपुर की जयसिंहपुर विधानसभा सीट पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन सपा के पूर्व विधायक अरुण वर्मा के नेतृत्व में हुआ। इस दौरान पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल को संबोधित एक छह सूत्रीय ज्ञापन उपजिलाधिकारी एसडीएम जयसिंहपुर को सौंपा। सपा नेताओं ने वर्तमान भाजपा सरकार पर जनता की समस्याओं के प्रति संवेदनहीन होने का आरोप लगाया। सौंपे गए ज्ञापन में समाजवादी पार्टी ने मुख्य रूप से छह गंभीर मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। पार्टी ने आरोप लगाया कि पेट्रोल, डीजल और रसेॉई गैस के दामों में लगातार बढ़ोतरी से आम जनता प्रभावित हो रही है। सपा का कहना है कि गरीब, किसान, मजदूर और मध्यमवर्गीय परिवार आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं, और सरकार राहत प्रदान करने में विफल रही है। ज्ञापन में जयसिंहपुर और सुलतानपुर सहित पूरे उत्तर प्रदेश में अयोधित बिजली कटौती का मुद्दा भी उठाया गया। सपा नेताओं ने बताया कि घंटों बिजली गुल रहने से बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं भीषण गर्मी में परेशानी झेल रही हैं। देश के करीब 22 लाख छात्रों के भविष्य से जुड़े नीट परीक्षा प्रश्नपत्र लीक मामले को भी प्रमुखता से उठाया गया। सपा नेताओं ने इसे युवाओं के सपनों पर सीधा हमला करार दिया। स्थानीय कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए सपा ने जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र के नगईपुर, बयैला, बनी, तबीपुर और इसूर जैसे कई गांवों में लगातार चोरी की वारदातों का उल्लेख किया।

सपा विधायक पर हमला, सोशल मीडिया पर वायरल हुई एक तस्वीर पर हंगामा

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। सपा विधायक महाराजी प्रजापति के आवास पर मंगलवार रात हुए हंगामे की जड़ सोशल मीडिया पर वायरल हुई एक तस्वीर और उस पर की गई टिप्पणियां बताई जा रही हैं। इंटरनेट मीडिया पर शुरू हुई बहस धीरे-धीरे इतनी बढ़ गई कि मामला विधायक आवास पर हुए हमले तक पहुंच गया। पिछले कई दिनों से दोनों पक्षों के बीच तीखी बयानबाजी चल रही थी।

जानकारी के अनुसार कुछ दिन पहले विधायक महाराजी प्रजापति एक कार्यक्रम में शामिल हुई थीं। इसी दौरान एक बुजुर्ग व्यक्ति के पैर छूने वाली तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। तस्वीर साझा करते हुए कुछ लोगों ने कटाक्ष भरी टिप्पणियां कीं। पोस्ट में सत्ता और प्रभाव को लेकर टिप्पणी की गई। इसके बाद विधायक समर्थकों और पोस्ट साझा करने वाले पक्ष के बीच लगातार जवाबी पोस्ट और टिप्पणियां होने लगीं। बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया



पर बहस बढ़ने के साथ दोनों पक्षों के बीच तनातनी भी बढ़ती गई। आरोप है कि एक-दूसरे को खुली चुनौती देने जैसी टिप्पणियां भी की गईं। इसी बीच बड़ी संख्या में लोग उस युवक के घर पहुंचे, जिस पर पोस्ट का समर्थन करने का आरोप था। हालांकि युवक घर पर नहीं मिला। वहां मौजूद परिजनों ने उससे दूरी होने की बात कही। बाद में कुछ लोगों को जानकारी मिली कि संबंधित

पूरी जानकारी के बाद में इसका जवाब दूंगी : महाराजी प्रजापति

इस हमले के बारे में जब विधायक महाराजी प्रजापति से बात की गई तो उन्होंने कहा कि रात में मैं घर पर नहीं थी। मैं उस पूरे मामले के बारे में पता कर रही हूँ। पूरी जानकारी के बाद मैं इसका जवाब दूंगी।

युवक विधायक आवास पर मौजूद है। इसके बाद कई लोग आवास विकास कॉलोनी स्थित विधायक आवास पहुंच गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वहां युवक को बाहर बुलाने की मांग होने लगी।

इसी दौरान माहौल गर्म हो गया और दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए। देखते ही देखते विवाद ने बड़ा रूप ले लिया। घटना के बाद देर रात तक इलाके में हलचल बनी रही। पुलिस ने पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि सोशल मीडिया पोस्ट से लेकर रात में हुई घटनाओं तक हर पहलू की गहन पड़ताल की जा रही है।

मेकेदातु जलाशय परियोजना को आगे बढ़ाने से रोकने के लिए तत्काल हस्तक्षेप करे केंद्र : विजय

» तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी को लिखा पत्र

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की कि वे कावेरी नदी पर प्रस्तावित मेकेदातु जलाशय परियोजना को आगे बढ़ाने से रोकने के लिए तत्काल हस्तक्षेप करें। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कदम सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों और कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण (सीडब्ल्यूडीटी) के फैसले का उल्लंघन करता है।

प्रधानमंत्री को लिखे एक विस्तृत पत्र में मुख्यमंत्री ने मेकेदातु परियोजना के लिए कर्नाटक द्वारा भूमि पूजन की घोषणा पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इस घटनाक्रम ने तमिलनाडु के उन किसानों में व्यापक चिंता पैदा कर दी है जो कृषि और आजीविका के लिए कावेरी नदी के पानी पर निर्भर हैं। तमिलनाडु सरकार ने तर्क दिया कि मेकेदातु परियोजना को कावेरी जल निकासी प्रणाली विभाग (सीडब्ल्यूडीटी) के अंतिम निर्णय के तहत कभी भी मंजूरी नहीं दी गई थी, जिसे



बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने 16 फरवरी, 2018 के अपने ऐतिहासिक फैसले में बरकरार रखा था। पत्र में इस बात पर जोर दिया गया कि कावेरी बेसिन को पहले से ही जल-कमी वाले बेसिन के रूप में वर्गीकृत किया गया है और उपलब्ध जल को तटवर्ती राज्यों के बीच पूरी तरह से आवंटित किया जा चुका है।

विजय ने अपने पत्र में कहा कि आप शायद इस बात से भलीभांति परिचित हैं कि कावेरी जल विवाद का समाधान लगभग तीन दशकों तक चले लंबे कानूनी संघर्ष के बाद प्राप्त हुआ था और 16 फरवरी, 18 का निर्णय कार्यान्वयन के अधीन है। मेकेदातु परियोजना न्यायाधिकरण द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं की सूची में नहीं है, जिसकी पुष्टि उपरोक्त निर्णय द्वारा की गई है।

विवादित बयान पर पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष फिर फंसे

» एससी आयोग ने राजा वडिंग को भेजा नोटिस

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

चंडीगढ़। पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष जसवीर सिंह गढ़ी ने राजा वडिंग को नोटिस भेजा है। वडिंग के अलावा श्री मुक्तसर साहिब के एसएसपी को 29 मई को जवाब के साथ पेश होने के लिए कहा गया है। वायरल आडियो में एक हजार में डेढ़, दो हजार में भेड़ जैसी आपत्तिजनक टिप्पणी सुनाई देने का दावा किया जा रहा है।

मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए आयोग ने

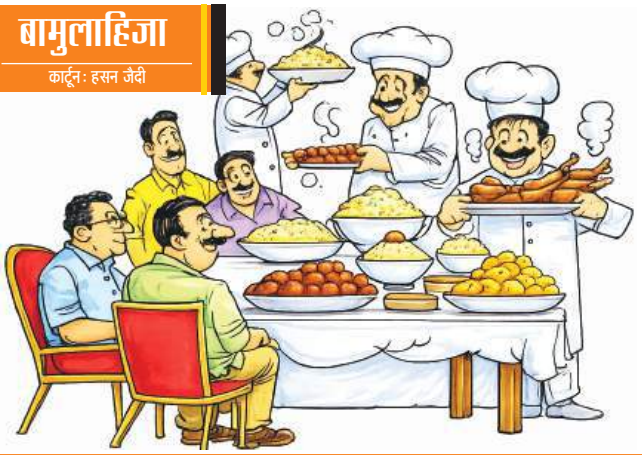


मुक्तसर के एसएसपी को 29 मई सुबह नौ बजे व्यक्तिगत रूप से पेश होने के निर्देश दिए हैं। आयोग की यह कार्यवाही सामाजिक सुरक्षा मंत्री डा. बलजीत कौर के भेजे संदेश के आधार पर

हुई है। पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग एक्ट-2004 की धारा 10 के तहत जांच शुरू कर दी गई है। आयोग ने पुलिस को आडियो सैंपल की फोरेंसिक जांच कराने और पूरी तथ्यात्मक रिपोर्ट सौंपने को कहा है। नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि आदेश न मानने पर आयोग सिविल अदालत जैसी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। वहीं राजा वडिंग ने एक्स पर पोस्ट कर आडियो को फर्जी बताया है। उन्होंने कहा कि करीब सात साल पुराना फर्जी आडियो अब एससी कमीशन के जरिए उन्हें बदनाम करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है।

बामुलाहिजा

कादम: हसन जैदी



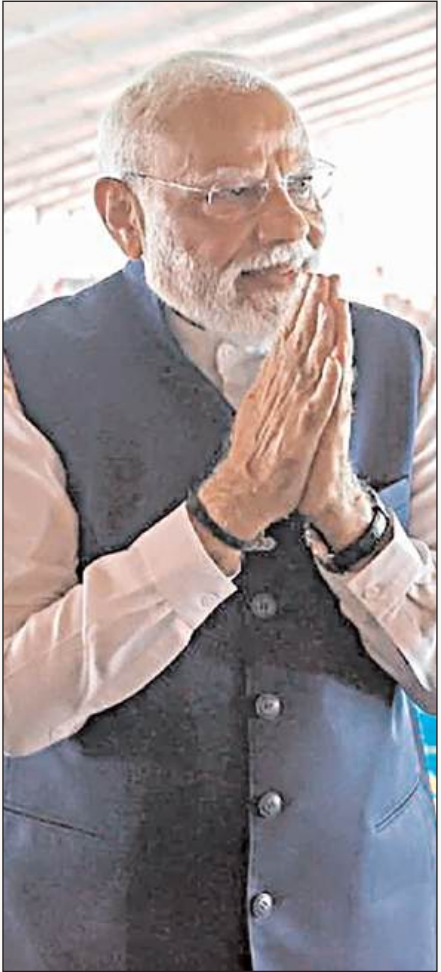
फाल्टा में हार टीएमसी की सियासत को बड़ा झटका

मोदी ने सराहा, अभिषेक ने उठाए सवाल

- » जहांगीर ने छोड़ा था मैदान
 - » भाजपा ने मारी बाजी टीएमसी चौथे पर
 - » सीपीआई दूसरे व कांग्रेस तीसरे पर रही
- 4पीएम न्यूज नेटवर्क

कोलकाता। बंगाल चुनाव की हार की टीएस अभी टीएमसी की कम भी नहीं हुई थी कि फाल्टा पुनर्मतदान में हार से उसका दर्द और बढ़ गया है। जहां इस जीत से भाजपा बहुत खुश है वहीं टीएमसी ने इसमें गलत तरीके अपनाने का आरोप लगाया है। भाजपा की जीत के बाद टीएमसी-भाजपा विवाद गहरा गया है, जिसमें टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने मतगणना की गति में 'स्पष्ट विसंगतियों' का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठाए हैं।

पश्चिम बंगाल के फाल्टा निर्वाचन क्षेत्र में 21 मई को हुए पुनर्मतदान में भाजपा के देबांशु पांडा की आरामदायक जीत के बाद रविवार को भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच एक बड़ा राजनीतिक विवाद छिड़ गया। पांडा ने 1 लाख से अधिक वोटों से जीत हासिल की, जबकि सीपीआई (एम) के शंभू नाथ कुर्मी 40,645 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे और कांग्रेस के अब्दुल रज्जाक मोल्ला को केवल 11084 वोट मिले। यह सब तब हुआ जब टीएमसी उम्मीदवार ने चुनाव से पहले ही नाम वापस ले लिया था। परिणामों की घोषणा के बाद, टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने फाल्टा निर्वाचन क्षेत्र में मतगणना के समय को लेकर चुनाव आयोग से स्पष्टीकरण मांगा। उन्होंने आरोप लगाया कि 4 मई को जब पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित किए गए, तब दोपहर 3:30 बजे तक केवल 2-4 दौर की मतगणना ही पूरी हुई थी। इसके विपरीत, फाल्टा में रविवार को उसी समय तक मतगणना के सभी 21 दौर पूरे हो चुके थे।



पश्चिम बंगाल की स्थिति पर चुनाव आयोग वयों आंखें मूंद लेता है : अभिषेक

उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि आज फाल्टा एसी में हुए पुनर्मतगणना से स्पष्ट विसंगतियां सामने आई हैं। आज दोपहर 3:30 बजे तक सभी 21 दौर पूरे हो चुके थे। 4 मई को इसी समय तक केवल 2-4 दौर ही हुए थे। देश को चुनाव आयोग से स्पष्टीकरण चाहिए। उन्होंने पश्चिम बंगाल की स्थिति पर चुनाव आयोग की आंखें मूंद लेने का भी आरोप लगाया और दावा किया कि पिछले 10 दिनों में फाल्टा से अधिक कार्यकर्ताओं को अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बावजूद दिनदहाड़े पार्टी कार्यालयों में तोड़फोड़ की गई। उन्होंने कहा कि हालांकि पिछले 10 दिनों में फाल्टा के हजारों श्रमिकों को अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, फिर भी चुनाव आयोग ने इस पर आंखें मूंद लीं। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बावजूद दिनदहाड़े पार्टी कार्यालयों में तोड़फोड़ की गई। चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके

बजाय, सीईओ, जिसका कथित तौर पर चुनाव आयोग द्वारा एसआईआर की आड़ में नाम हटाने और चुनावी प्रक्रिया में हेरफेर करने के लिए इस्तेमाल किया गया था, को नई पश्चिम बंगाल सरकार में मुख्य सचिव नियुक्त कर दिया गया, उस समय जब फाल्टा में आदर्श आचार संहिता अभी भी लागू थी और मतदान प्रक्रिया पूरी भी नहीं हुई थी। इसे चिंताजनक बताते हुए, उन्होंने आगे आरोप लगाया कि तृणमूल और भाजपा को छोड़कर अन्य राजनीतिक दलों के मतगणना एजेंटों को कथित तौर पर 4 मई को भारतीय चुनाव आयोग के तहत तैनात अधिकारियों और केंद्रीय बलों द्वारा स्थल से बाहर निकाल दिया गया था। उन्होंने आगे कहा कि यह बेहद चिंताजनक है और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों के मूल सिद्धांतों पर सीधा प्रहार है। जब तक भ्रष्ट अधिकारियों को जवाबदेह नहीं ठहराया जाता और मतगणना प्रक्रिया का स्वतंत्र सीसीटीवी ऑडिट नहीं कराया जाता, जनादेश की विश्वसनीयता पर सवाल और भी बढ़ते जाएंगे।

लोकतंत्र की जीत, धमकियों की हार : मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की शानदार जीत की सराहना की। इस सीट को लंबे समय से टीएमसी का गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन भाजपा ने यहां तृणमूल कांग्रेस को एक लाख से ज्यादा वोटों से करारी शिकस्त दी। मोदी ने इस नतीजे को लोकतंत्र की जीत और पश्चिम बंगाल में बीजेपी के शासन पर जनता की मुहर बताया। प्रधानमंत्री ने लिखा, फलता की

जनता ने अपना फैसला सुना दिया है! लोकतंत्र की जीत हुई है और धमकियों की हार। फलता में रिकॉर्ड अंतर से जीत हासिल करने के लिए श्री देबांशु पांडा जी को बधाई। उन्होंने आगे कहा, यह पश्चिम बंगाल की जनता का भाजपा के प्रति अटूट विश्वास दिखाता है। लोग पश्चिम बंगाल सरकार के हर क्षेत्र में किए जा रहे बेहतरीन कामों को देख रहे हैं, और इसीलिए उन्होंने हमें और आशीर्वाद देने का फैसला किया है। मोदी ने पूरे राज्य में

भाजपा कार्यकर्ताओं को उनके शानदार काम के लिए बधाई दी और कहा कि पार्टी बंगाल की प्रगति के लिए लगातार काम करती रहेगी। फलता विधानसभा सीट को लंबे समय से टीएमसी के राजनीतिक रूप से मजबूत डायमंड हार्बर बेल्ट का हिस्सा माना जाता रहा है। 21 में पार्टी ने लगभग 57 प्रतिशत वोटों के साथ इस सीट पर आसानी से जीत हासिल की थी। लेकिन, इस उपचुनाव ने चुनावी तस्वीर को पूरी तरह से बदल दिया।

29 अप्रैल को हुए चुनाव के दौरान मिली थी गड़बड़ी

चुनाव आयोग ने 29 अप्रैल को हुए चुनाव के दौरान बूथों पर परफ्यूम जैसी चीजों, स्याही के निशान और चिपकने वाली टेप के कथित इस्तेमाल की शिकायतें मिलने के बाद, 21 मई को सभी 285 बूथों पर दोबारा वोटिंग का आदेश दिया था। यह दोबारा वोटिंग कड़ी सुरक्षा के बीच कराई गई।

बंगाल में अभी रहेगी केंद्रीय सुरक्षा बल

केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के अनुरोध पर पश्चिम बंगाल में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 500 कंपनियों की तैनाती 20 जून तक बढ़ा दी है। गृह मंत्रालय का यह फैसला चुनाव के बाद राज्य के संवेदनशील क्षेत्रों में कानून-व्यवस्था बनाए रखने में स्थानीय पुलिस की सहायता के लिए लिया गया है। केंद्र सरकार ने गुरुवार को राज्य सरकार के अनुरोध पर पश्चिम बंगाल में केंद्रीय बलों की तैनाती एक और महीने के लिए बढ़ाने का फैसला किया। गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में

सरकार ने कहा कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 500 कंपनियां 20 जून तक पश्चिम बंगाल में तैनात रहेंगी। आदेश में कहा गया है कि तैनाती में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 200 कंपनियां, सीमा सुरक्षा बल की 150 कंपनियां, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस और सशस्त्र सीमा बल (SSB) की 50-50 कंपनियां शामिल हैं। अधिसूचना में कहा गया है कि पश्चिम बंगाल सरकार के अनुरोध पर इस मंत्रालय में विचार किया गया है। इसमें आगे कहा

गया है कि पश्चिम बंगाल सरकार से अनुरोध है कि वह राज्य के भीतर सीपीएफएस की तैनाती के संबंध में आवश्यक परिवहन, रसद, आवास और अन्य व्यवस्थाओं को बलों की परिचालन आवश्यकताओं के अनुसार राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए। यह घटनाक्रम मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी द्वारा केंद्रीय बलों की तैनाती को निर्धारित दो महीने की अवधि से आगे बढ़ाने के लिए मुख्य सचिव और गृह सचिव से किए गए अनुरोध के कुछ दिनों बाद सामने आया है। मुख्यमंत्री ने राज्य में चुनाव

के बाद की स्थिति की समीक्षा के लिए अधिकारियों के साथ बैठक की थी, जिसके बाद उन्होंने यह अनुरोध किया। गौरतलब है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी एक चुनावी रैली में यह भी कहा था कि सीपीएफएस (केंद्रीय सुरक्षा बल) पश्चिम बंगाल में सामान्य 60 दिनों की अवधि से आगे भी तैनात रहेंगे। बाद में, एक अधिकारी ने यह भी बताया कि केंद्रीय बल राज्य के संवेदनशील क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बनाए रखने में स्थानीय पुलिस की सहायता पर ध्यान केंद्रित करेंगे।



Sanjay Sharma

editor.sanjaysharma

@Editor_Sanjay

जिद... सच की

हीट वेब प्रकृति के साथ खिलवाड़ का नतीजा

मई का महीना गर्मी की वजह से जानलेवा हो गया है। पूरे देश में हर जगह हीटवेब चल रही है। वर्ष 2026 की गर्मी केवल एक मौसमी घटना नहीं, बल्कि मानव सभ्यता के सामने खड़ी एक गंभीर चेतावनी बनकर सामने आई है। अप्रैल-मई के दौरान भारत सहित दक्षिण एशिया के अनेक हिस्सों में पड़ी रिकॉर्ड हीटवेब ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जलवायु परिवर्तन अब भविष्य का संकट नहीं, वर्तमान की भयावह वास्तविकता है। हीटवेब का सबसे बड़ा कारण केवल बढ़ता तापमान नहीं, बल्कि वह विकास मॉडल है जिसने धरती की प्राकृतिक ढाल को कमजोर कर दिया। जंगल सदियों से पृथ्वी के प्राकृतिक एयर कंडीशनर रहे हैं। वे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, वाष्पोत्सर्जन द्वारा वातावरण को शीतल रखते हैं और वर्षा चक्र को संतुलित बनाए रखते हैं।

लेकिन विडंबना है कि विकास के नाम पर जंगलों का तेजी से विनाश हुआ। दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य भारत के अनेक क्षेत्रों में तापमान 46 से 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। कई शहरों में बिजली की मांग ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। सड़कें सूनी दिखने लगीं, श्रमिकों का श्रम ठहरने लगा और बच्चों, बुजुर्गों तथा गरीब तबकों के सामने जीवन बचाने की चुनौती खड़ी हो गई। यह संकट अचानक नहीं आया। यह दशकों से प्रकृति के साथ किए गए असंतुलित व्यवहार, अंधाधुंध शहरीकरण, जंगलों की कटाई, संसाधनों के दोहन और सुविधावादी जीवनशैली का परिणाम है। प्रकृति ने बार-बार संकेत दिए, लेकिन विकास की अंधी दौड़ में हमने उन संकेतों को अनसुना किया। आज वही उपेक्षित चेतावनियां लू बनकर हमारे सामने खड़ी हैं। हर वर्ष लाखों हेक्टेयर वन क्षेत्र समाप्त हो रहे हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि स्थानीय स्तर पर तापमान बढ़ा, नमी कम हुई, वर्षा चक्र प्रभावित हुआ और गर्म हवाओं की अवधि लंबी होती गई। आज शहर कंक्रीट के जंगल बन चुके हैं। महानगरों में हरित क्षेत्र सिक्कड़ते जा रहे हैं और उनकी जगह सीमेंट, डामर और शीशे की ऊंची इमारतें ले रही हैं। इससे अर्बन हीट आइलैंड प्रभाव तेजी से बढ़ा है। शहर अब आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में कई डिग्री अधिक गर्म हो चुके हैं। कंक्रीट दिनभर सूर्य की ऊष्मा को सोखता है और रात में धीरे-धीरे छोड़ता है। परिणामस्वरूप रातें भी गर्म होती जा रही हैं और शरीर को राहत नहीं मिल पाती।

Sanjay

(इस लेख पर आप अपनी राय 9559286005 पर एसएमएस या info@4pm.co.in पर ई-मेल भी कर सकते हैं)

ऊर्जा की नई किरण भारत-ओमान समुद्री पाइपलाइन

प्रमोद जोशी

होर्मुज जलसंधि का रास्ता बंद होने और भारत में ऊर्जा-संकट के बादल गहराने से जुड़ी खबरों के बीच एक खबर को ज्यादा सुर्खियां नहीं मिल पाई कि भारत, गहरे समुद्र में एक गैस पाइपलाइन परियोजना पर विचार कर रहा है, जो हमें ओमान से जोड़ेगी। भारत सरकार ने अब इस पर तेजी से काम करना शुरू किया है। हाल में कुछ मीडिया स्रोतों ने पेट्रोलियम मंत्रालय के एक अधिकारियों को उद्धृत करते हुए खबर दी है कि मंजूरी मिली, तो करीब 4.8 अरब डॉलर की लागत से बनने वाली परियोजना खाड़ी क्षेत्र से निर्बाध गैस आपूर्ति सुनिश्चित करेगी। परियोजना को समय से हरी झंडी मिली, तब भी इसे पूरा होने में पांच से सात साल लगेंगे। उसके पहले इसके सभी आर्थिक और तकनीकी पहलुओं पर विचार करना भी जरूरी होगा। सौ साल से ज्यादा समय से इसकी परिकल्पना चल रही है।

इस पर यूपीए सरकार के दौर में भी बात चली थी। ओमान की वेबसाइट 'मस्कट डेली' की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत सरकार नई दिल्ली स्थित निजी क्षेत्र के कंसोर्शियम साउथ एशिया गैस एंटरप्राइज (सेज) द्वारा प्रस्तुत पूर्व-व्यवहार्यता अध्ययन पर विचार कर रही है, जो समुद्र तल की स्थितियों का अध्ययन करने के लिए 'टेस्ट-सेक्शन' बिछा रहा है। 'सेज' ने प्रस्तावित मार्ग पर लगभग 3,000 मीटर परीक्षण पाइपलाइन बिछाकर प्रारंभिक चरण का तकनीकी सत्यापन कर लिया है, जिस पर लगभग 25 करोड़ रुपये की लागत आई है। यह पाइपलाइन इंजीनियरों के लिए चुनौती भी होगी, क्योंकि कुछ जगहों पर यह करीब साढ़े तीन किलोमीटर तक की गहराई पर बिछानी पड़ेगी, जो अब तक समुद्र के नीचे बिछाई गई दुनिया की किसी भी पाइपलाइन की तुलना में चार गुना अधिक गहरी होगी। इस अध्ययन का उद्देश्य समुद्र तल की स्थितियों का आकलन करना और इंजीनियरिंग

संभावनाओं की पुष्टि करना है। भारत का पेट्रोलियम मंत्रालय, सरकारी कंपनियों गेल, इंजीनियर्स इंडिया और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश देगा।

रिपोर्ट सकारात्मक हुई, तो ओमान के साथ गैस आपूर्ति, वित्तपोषण और परियोजना कार्यान्वयन पर औपचारिक बातचीत का रास्ता खुलेगा। पश्चिम एशिया से भारत तक समर्पित पाइपलाइन बनी, तो हम किसी ट्रांजिट देश या समुद्री अवरोध बिंदु पर निर्भर नहीं रहेंगे और किफायती लागत पर गैस की आपूर्ति लगातार जारी रहेगी। मिडिल-ईस्ट-इंडिया डीप-वाटर पाइपलाइन



(एमआईडीपी) अरब सागर के नीचे लगभग 2,000 किलोमीटर तक लंबी होगी, जो ओमान को भारत के गुजरात तट से जोड़ेगी। इस परियोजना से भारत को ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, ईरान, तुर्कमेनिस्तान और कतर से गैस आपूर्ति प्राप्त करने में मदद मिलेगी। वर्ष 25 में भारत के एलएनजी आयात का लगभग दो-तिहाई हिस्सा होर्मुज जलसंधि से होकर गुजरा था। इस साल फरवरी के अंत में होर्मुज संकट शुरू होने के बाद, वैश्विक एलएनजी आपूर्ति में 20 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई, जिससे कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई। इस गिरावट के कारण भारत के उर्वरक संयंत्रों, बिजलीघरों और उद्योगों की आपूर्ति में अचानक लगे झटकों ने चिंता पैदा की है। खनिज तेल की ऊंची कीमतों ने आयात लागत को पहले ही बढ़ा दिया है। इस पृष्ठभूमि में, टैंकरों पर निर्भरता को कम करने और प्राकृतिक गैस का स्थिर प्रवाह सुनिश्चित

करने के लिए दशकों पुरानी इस परियोजना को पुनर्जीवित किया जा सकता है। इस परियोजना से प्रतिदिन लगभग 31 मिलियन मानक घन मीटर प्राकृतिक गैस की आपूर्ति होने की उम्मीद है। वर्तमान राष्ट्रीय गैस खपत लगभग 190 से 195 मिलियन मानक घन मीटर प्रतिदिन है, जो औद्योगिक और शहरी गैस नेटवर्क के विस्तार और उर्वरक क्षेत्र की मांग में वृद्धि पर भी निर्भर है। 2030 तक, यह मांग 290 से 300 मिलियन वर्ग मीटर प्रतिदिन तक पहुंचने का अनुमान है। भारत को खाड़ी देशों से जोड़ने वाली समुद्री पाइपलाइन की अवधारणा नई नहीं है। 1990 के

दशक से इस प्रस्ताव के विभिन्न रूप समय-समय पर सामने आते रहे हैं, लेकिन द्विपक्षीय वार्ता की जटिलता, वित्तपोषण की अनिश्चितता और अपर्याप्त राजनीतिक उत्साह के कारण वे उठे बस्ते में चले गए।

बहरहाल इसबार की पहल तीन कारणों से उत्साहवर्धक है। एक, समुद्र में पाइप बिछाने की तकनीक में काफी प्रगति हुई है। पर्याप्त भू-राजनीतिक झटकों की वजह से राजनीतिक इच्छाशक्ति पैदा हो गई है, और तीसरे, सरकारी संस्थाओं को काम के औपचारिक निर्देश मिले हैं। यह परियोजना अब केवल सैद्धांतिक मनोकामना नहीं है, बल्कि सक्रिय इंजीनियरिंग और डिप्लोमैटिक प्रयास है। इस पाइपलाइन की संरचना से भारत को ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, ईरान, तुर्कमेनिस्तान और कतर से प्राकृतिक गैस प्राप्त करने का अवसर मिल सकता है।

संजय दुबे (वरिष्ठ पत्रकार)

हज! हर इस्लाम को मानने वाला का एक सपना। एक ऐसा सपना जिसको हर मुसलमान देखता है गरीब हो चाहे अमीर। भारत से पहली बार हज पर कौन गया? कब गया? इसका कोई लिखित प्रमाण फिलहाल कहीं नहीं मिलता, लेकिन 'अरब न्यूज' के अनुसार 664 ई. से 712 ई. के बीच मुमकिन है कि कुछ लोग हज पर गये हो सकते हैं, ऐसा उसका इसलिए मानना है क्योंकि इसी के आस पास सिंध पर इस्लामी आक्रमण होता है खैर! पहली बार हज पर कौन गया? इसका भले जिक्र कहीं न हो। पर, मुगलों ने भारत से इसके लिए जहाज चलवाए थे। इसका बाकायदा लिखत -पढंत में हिसाब किताब है। 1576 ईस्वी में हिंदुस्तान पर मुगलों की हुकूमत थी। हिंदुस्तान के सिंहासन पर मुगल बादशाह अकबर बैठे थे।

उस वक्त इनके ही खानदान की कुछ महिलाओं ने हज करने का फैसला किया। इस बात की सूचना अकबर को दी गई जिसे सुन अकबर काफी हैरान हुए आखिर! उस समय पुरुष के लिए ही हज बड़ी बात थी फिर, ये तो महिलाएँ थी। अकबर इनको इजाजत दे देते हैं। इस हज पर जाने वाली महिलाओं में शामिल थी -अकबर की बुआ गुलबदन बेगम, उनकी माँ हमीदा बेगम उर्फ हाजी बेगम और उनकी एक पत्नी सलीमा सुल्ताना बेगम, इनको इस पवित्र यात्रा पर ले जाने के लिए दो आलीशान मुगल जहाज दिए गए। जिनके नाम थे सलीमी और इलाही। इन शाही महिलाओं के साथ सोने, चांदी और जेवरत से भरे भारी संदूक भी गए। ये महिलाएँ मक्का-मदीना पहुँचती हैं और वहाँ पूरे 7 साल तक रह कर दान पुण्य करती हैं। इनके दान के किस्से वहाँ के रेगिस्तान

भारतीय हाजियों के हज का सफरनामा



की रेत की तरह समूचे अरब जगत में फैल जाते हैं। इस दान के चलते ऑटोमन सुल्तान मुराद तक इनसे नाराज हो जाता है। इतना नाराज होता है कि इनको निकालने के लिए बाकायदा 4 बार शाही फरमान तक निकाल देता है। मुगल काल से लगाये 18वीं सदी तक भारत के हज यात्रियों के पास दो ही रास्ते थे।

एक था समुद्री रास्ता और दूसरा था जमीनी। जमीनी रास्ता लम्बा और कठिन तो था ही साथ ही बीच में कुछ ऐसे क्षेत्र भी थे जहाँ सब कुछ हज यात्रियों का लुट जाता था। कभी-कभी सामान के साथ इनको जान भी गंवानी पड़ती थी। ऐसा होने के चलते भारतीय हज यात्रियों का पसंदीदा रास्ता समुद्री ही था। इस रास्ते की शुरुआत अरब सागर से होती थी। फिर लाल सागर और फारस की खाड़ी से होते हुए अरब पहुँचते थे। समुद्री रास्ता भी बहुत ज्यादा सुरक्षित नहीं था। इन रास्तों पर 16वीं सदी में एक बार ऐसा समुद्री लुटेरों का आतंक बड़ा कि मुगल दरबार के धार्मिक विद्वानों ने इन परिस्थितियों में हज की अनिवार्यता को जरूरी ही नहीं माना। अब इन सारी बातों से पता चलता है कि भारत से हज के लिए जाना उस

समय खतरे से खाली नहीं था। इन सारी दिक्कतों को देखते हुए मुगल बादशाहों ने उस वक्त एक अहम फैसला लिया। मुगल बादशाहों ने जहाँ खुद तो हज नहीं किया पर प्रजा के लिए उन्होंने मुफ्त हज यात्रा की शुरुआत कर दी। इतना ही नहीं उनके भोजन पानी के भी फ्री इंतजाम किये। बादशाह अकबर ने इसकी शुरुआत की। उनके दिल्ली के सिंहासन पर बैठते ही उन्होंने भारतीय हज यात्रियों के लिए दो इंतजाम किये।

भारत से जहाँ इनको फ्री में ले जाने की व्यवस्था की, वहीं मक्का के भीतर रहने के लिए एक आश्रम भी बनवाया। इस आश्रम के भीतर यहाँ से गए हज यात्रियों के लिए फ्री में रुकने के इंतजाम किये। सन 1570 के आस पास एक सरदार को 'मीर हज' नियुक्त किया। मीर हज का काम ही था हज यात्रियों के रुकने और आने-जाने का इंतजाम करना। अकबर के दरबार में एक बड़े ही नामी सरदार रहा करते रहते थे। नाम था अब्दुरहीम खानखाना। अकबर ने इनको आदेश दे रखा था कि मुगलिया सल्तनत के तीन जहाज रहीमी, करीमी और सलारी को रिजर्व रखें। ये जहाज हमेशा बस हज के लिए

ही काम में लिए जाते थे। ये जहाज बाब-उल-मक्का यानि आज का सूत, से जेद्दाह तक फ्री में हज यात्रियों को लेकर जाता था। ये परम्परा सम्राट जहाँगीर से लगाये शाह जहाँ तक अनवरत चलती रही। शाहजहाँ भी मीर हज नियुक्त करते थे। साथ ही मक्का में हर साल दान भी भेजते थे। अब बात भारत के सबसे ज्यादा धर्मांध माने जाने बादशाह औरंगजेब की। इनके दौर में हर साल दो जहाज सैकड़ों हजयात्रियों को लेकर लाल सागर के जरिये हज कराते थे। औरंगजेब की एक बेटी थी जिसका नाम था जेब-उन -निशा।

जैबुनिशा ने 1676 ईस्वी में इस्लामिक विद्वान सफी बिन वली अल कजनवी को भी इसी तरह से हज कराया। जिसका वर्णन उन्होंने अपने ग्रन्थ अनीस -अल-हज में लिखा है। इसे आज भी मुंबई के 'प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय' में देखा जा सकता है। सऊदी अरब के एक आंकड़ों के अनुसार 1958 से 1968 तक 10 सालों में भारत से 200,100 लोग हज पर गए। जबकि यमन से 3,21,268 और संयुक्त अरब गणराज्य से 2,320.70 हज यात्री वहाँ पहुंचे। इन आंकड़ों को देखकर लगता है कि औसतन हर साल 20 हजार हज यात्री उन 10 सालों में गये। सन 24 में भारत से मक्का 1,75,00 लोग हज करने गए। ये आंकड़ें बताते हैं कि तकनीक और बेहतर सेवाओं के चलते इस यात्रा में लोगों का शामिल होना बढ़ा है न कि उनकी खुद की जोखिम लेकर यात्रा करने की क्षमता के कारण। खुद सोच कर देखिए! जब बादशाहों को अपने जहाज से हज करके आने में साल भर लग जाता था तब पैदल जाने वाले हाजियों को कितना समय लगता रहा होगा? लेकिन तब भी जाने वाले ही हज पर जाते थे और अब भी शायद वही जाते हैं जिन्हें 'सरकार-ए-मदीना' बुलाते हैं।

डिहाइड्रेशन

का गर्मियों में बढ़ जाता है ज्यादा खतरा

थोड़ा-थोड़ा भोजन करें
गर्मी के दिनों में अपच और गैस की समस्या से बचे रहने के लिए एक साथ ज्यादा खाने से अच्छा है कि आप थोड़ा-थोड़ा भोजन करें। गर्मियों में भारी और तैलीय भोजन का पाचन कठिन हो सकता है, इसलिए अधिक मात्रा में तरल चीजों और कम मसाले वाली चीजें खाएं।

पाचन विकारों का जोखिम

अत्यधिक गर्मी आपके पाचन तंत्र पर भी नकारात्मक असर डाल सकती है। शरीर का निर्जलित होना आपके जोखिमों को और भी बढ़ा देती है। व्यक्ति के शरीर का गर्मी के लंबे समय तक संपर्क में रहने से पेट में ऐंठन और दर्द की दिक्कत होने लगती है। इसके अलावा गर्मी के दिनों में भोजन के रखरखाव में बरती गई असावधानी के कारण भी फूड पॉइजनिंग हो सकती है। और गर्मी में पानी की कमी भी हो जाती है। इस तरह की दिक्कतों से बचाव में कुछ उपाय मददगार हो सकते हैं।



स्वस्थ आहार जरूरी

जंक फूड और बासी चीजों के सेवन से बचना गर्मियों में सेहत को ठीक रखना जरूरी है। घर पर बना ताजा भोजन और फलों-सब्जियों को धोकर ही सेवन करें। फूड पॉइजनिंग की समस्या से बचे रहने के लिए लंबे समय तक रखे भोजन को न खाएं। गर्मियों में ज्यादा तली-भुनी चीजों के सेवन से भी बचना जरूरी है। गर्मी में भोजन जल्दी खराब हो जाते हैं और उनमें बैक्टीरिया के बढ़ने का खतरा रहता है जो खाद्य जनित बीमारियों का कारण बन सकते हैं।

शरीर को रखें हाइड्रेटेड

गर्मियों में खूब मात्रा में पानी पीते रहना अच्छी सेहत के लिए जरूरी है। पानी पीने से न सिर्फ आप डिहाइड्रेशन से बचते हैं साथ ही पाचन विकारों का जोखिम भी कम होता है। प्रतिदिन कम से कम 8 से 10 गिलास पिएं। इसके अलावा फलू के जूस, नारियल पानी और ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशंस (ओआरएस) जैसे पेय भी पाचन से संबंधित समस्याओं से बचाने में मददगार हैं।

शहर में तेजी से बढ़ती गर्मी की समस्या सेहत के लिए कई प्रकार से चुनौतीपूर्ण हो सकती है। उच्च तापमान के कारण हीट स्ट्रोक और निर्जलीकरण (डिहाइड्रेशन) होने का खतरा रहता है। गर्मियों का ये मौसम पाचन स्वास्थ्य के लिए भी चुनौतीपूर्ण माना जाता है। बढ़ती गर्मी के साथ अपच, गैस, उल्टी, दस्त और पेट में दर्द से संबंधित समस्याओं का खतरा काफी बढ़ जाता है। खराब आहार, शरीर में पानी की कमी और शरीर की अत्यधिक गर्मी जैसे कई कारक गर्मियों में पाचन समस्याओं का कारण बन सकते हैं। गर्मी के मौसम में पाचन क्रिया भी धीमी हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप कब्ज, एसिड रिफ्लक्स और फूड पॉइजनिंग के मामले बढ़ने लगते हैं। डॉक्टर कहते हैं, इस मौसम में सभी लोगों को पाचन को ठीक रखने के लिए उपाय करते रहना जरूरी है। कुछ आसान से उपायों की मदद से आप पाचन स्वास्थ्य से संबंधित विकारों को कम कर सकते हैं।



हंसना मना है

पति- अगर मैं मर गया तो तुम दूसरी शादी करोगी? वाईफ- नहीं, मैं अपनी बहने के साथ पूरी जिन्दगी रह लूंगी। वाईफ- अगर मैं मर गयी तो तुम दूसरी शादी करोगे? हसबैंड - मैं भी तुम्हारी बहने के साथ पूरी जिन्दगी रह लूंगा।

पहला दोस्त- 'यार मैं जिस लड़की को चाहता हूँ, उसने मुझसे शादी नहीं की। दूसरा दोस्त- 'तुमने उसे बताया की तेरा चाचा करोड़पति है? पहला दोस्त - 'हां मैंने बताया था। दूसरा दोस्त - 'तो फिर पहला दोस्त - अब वो मेरी चाची है।

आजकल दो चीज सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलती है.. एक तो जंगल में घुमता सफेद हाथी..! और दूसरा बिना अफेयर वाला जीवन साथी।

पति मरते वक्त बीवी से- अलमारी से तेरा गोल्ड सेट मैंने ही चोरी किया था! बीवी रोते हुए- कोई बात नहीं जी, पति- तेरे भाई ने तुझे 1 लाख अमानत दी थी, वो भी मैंने गायब की! बीवी- मैंने आपको माफ किया! पति- तेरी कमेटी के पैसे भी मैंने ही चोरी किये थे! बीवी- कोई बात नहीं जी, आपको जहर भी मैंने ही दिया है।

टीचर- बताओ सबसे नशीला पदार्थ कौन सा होता है? पप्पू- किताब है सर, साला खोलते ही नींद आ जाती है।

कहानी मृत्यु एक अटल सत्य है

राधेश्याम स्वभाव का बड़ा ही शांत एवम सुविचारों वाला व्यक्ति था। उसके परिवार में माता-पिता, पत्नी एवम दो बच्चे थे। सभी से वो बेहद प्यार करता था। इसके अलावा वो कृष्ण भक्त था और सभी पर दया भाव रखता था। राधेश्याम अपने कृष्ण को देख भी सकता था और बातें भी करता था। इसके बावजूद उसने कभी ईश्वर से कुछ नहीं मांगा। राधेश्याम कृष्ण को अपने मित्र की तरह ही पुकारता था और उनसे अपने विचारों को बांटता था। एक दिन राधेश्याम के पिता की तबियत अचानक खराब हो गई। अस्पताल में उसने सभी डॉक्टरों के हाथ जोड़े। अपने पिता को बचाने की मिन्नतें कीं। लेकिन सभी ने उससे कहा कि वो ज्यादा उम्मीद नहीं दे सकते। तभी राधेश्याम ने कृष्ण को पुकारा। कृष्ण दौड़े चले आये। राधेश्याम ने कहा- मित्र! तुम तो भगवान हो मेरे पिता को बचा लो। कृष्ण ने कहा- मित्र! ये मेरे हाथों में नहीं हैं। अगर मृत्यु का समय होगा तो होना तय है। इस पर राधेश्याम नाराज हो गया और कृष्ण से लड़ने लगा, भगवान ने उसे बहुत समझाया पर उसने एक ना सुनी। कृष्ण ने कहा- मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ लेकिन इसके लिए तुम्हें एक कार्य करना होगा। कैसा कार्य? कृष्ण ने कहा- तुम्हें किसी एक घर से मट्टी भर ज्वार लानी होगी और ध्यान रखना होगा कि उस परिवार में कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। राधेश्याम ने कई दरवाजे खटखटाए। हर घर में ज्वार तो होती लेकिन ऐसा कोई नहीं होता जिनके परिवार में किसी की मृत्यु ना हुई हो। तब उसे अहसास हुआ कि मृत्यु एक अटल सत्य है। इससे कोई नहीं भाग सकता। और वो अपने व्यवहार के लिए कृष्ण से क्षमा मांगता है और निर्णय लेता है जब तक उसके पिता जीवित हैं उनकी सेवा करेगा। थोड़े दिनों बाद पिता स्वर्ग सिंघार जाते हैं। उसे दुःख तो होता है लेकिन ईश्वर की दी उस सीख के कारण उसका मन शांत रहता है।

कहानी से सीख- दोस्तों इसी प्रकार हम सभी को इस सच को स्वीकार करना चाहिये कि मृत्यु एक अटल सत्य है उसे नकारना मुर्खता है। दुःख होता है लेकिन उसमें फंस जाना गलत, केवल आप ही उस दुःख से पीड़ित नहीं हैं अपितु सम्पूर्ण मानव जाति उस दुःख का सामना करती ही है। ऐसे सच को स्वीकार कर आगे बढ़ना ही जीवन है। कई बार हम अपने किसी खास के चले जाने से इतने बेबस हो जाते हैं कि सामने खड़ा जीवन और उससे जुड़े लोग हमें दिखाई ही नहीं पड़ते। ऐसे अंधकार से निकलना मुश्किल हो जाता है। जो मनुष्य मृत्यु के सत्य को स्वीकार कर लेता है उसका जीवन भार विहीन हो जाता है और उसे कभी कोई कष्ट तोड़ नहीं सकता।

7 अंतर खोजें

जानिए कैसा रहेगा कल का दिन

लेखक प्रसिद्ध ज्योतिषविद हैं। सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए कॉल करें-9837081951

मेघ 	भाग्य का साथ रहेगा। नौकरी में अनुकूलता रहेगी। प्रसन्नता रहेगी। कुबुद्धि हावी रहेगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। विवाद से दूर रहें। कुसंगति से बचें। निवेश शुभ रहेगा।	तुला 	व्यापार-व्यवसाय ठीक चलेगा। शत्रु शांत रहेंगे। ऐश्वर्य पर खर्च होगा। अप्रत्याशित खर्च सामने आएंगे। कर्ज लेना पड़ सकता है। पुराना रोग उभर सकता है।
वृषभ 	शेयर मार्केट व म्युचुअल फंड में सोच-समझकर हाथ डालें। जल्दबाजी न करें। समय अनुकूल है। यात्रा मनोरंजक रहेगी। विद्यार्थी वर्ग सफलता प्राप्त करेंगे।	वृश्चिक 	प्रेम-प्रसंग में अनुकूलता रहेगी। शुभ समाचार मिल सकता है। व्यावसायिक यात्रा लाभदायक रहेगी। मित्रों का सहयोग कर पाएंगे। मान-सम्मान मिलेगा।
मिथुन 	वर्ध भगदौड़ रहेगी। समय का अपव्यय होगा। दूर से दुःखद समाचार प्राप्त हो सकता है। विवाद से वलेश होगा। काम में मन नहीं लगेगा। लेन-देन में जल्दबाजी न करें।	धनु 	कीमती वस्तुएं संभालकर रखें। नई योजना बनेगी। कार्यप्रणाली में सुधार होगा। कारोबारी नए अनुबंध हो सकते हैं, प्रयास करें। आय में वृद्धि होगी।
कर्क 	कीमती वस्तुएं संभालकर रखें। शारीरिक कष्ट संभव है। परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी। कोई ऐसा कार्य न करें जिससे कि नीचा देखना पड़े।	मकर 	धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। पूजा-पाठ में मन लगेगा। लाभ के अवसर हाथ आएंगे। प्रसन्नता रहेगी। यात्रा मनोनुकूल लाभ देगी। राजभार रहेगा।
सिंह 	दूर से शुभ समाचार प्राप्त होगा। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। घर में प्रतिष्ठित अतिथियों का आगमन हो सकता है। व्यय होगा। जोखिम उठाने का साहस कर पाएंगे।	कुम्भ 	कीमती वस्तुएं संभालकर रखें। शारीरिक शिथिलता रहेगी। काम में मन नहीं लगेगा। किसी अपने का व्यवहार प्रतिकूल रहेगा। पार्टनरों से मतभेद हो सकते हैं।
कन्या 	व्यावसायिक यात्रा से लाभ होगा। अप्रत्याशित लाभ हो सकता है। निवेशादि शुभ रहेंगे। कारोबार में वृद्धि के योग हैं। किसी बड़ी समस्या का हल प्राप्त होगा।	मीन 	किसी वरिष्ठ व्यक्ति का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। कारोबारी लाभ में वृद्धि होगी। नौकरी में शांति रहेगी। सहकर्मियों का साथ मिलेगा। धनार्जन होगा। विवेक से कार्य करें।

हालीवुड

बायोपिक

पाकिस्तानी क्रिकेटर का किरदार निभाएंगे फरहान अख्तर!



फरहान अख्तर इन दिनों रणवीर सिंह के साथ डॉन 3 विवाद को लेकर चर्चाओं में हैं। इसी बीच उनके काम से जुड़ी भी एक खबर आ रही है। फरहान जल्द ही क्रिकेटर लाला अमरनाथ पर बन रही फिल्म में कैमियो रोल कर सकते हैं। फरहान अख्तर जल्द ही फिल्म निर्माता आशुतोष गोवारिकर के आगामी प्रोजेक्ट में नजर आ सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक क्रिकेटर लाला अमरनाथ की बायोपिक में फरहान कैमियो रोल में नजर आएंगे। वह फिल्म में एक पाकिस्तानी क्रिकेटर की भूमिका में दिखाई दे सकते हैं। इसमें उनका किरदार लाला अमरनाथ के बेहद नजदीक है और भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है। हालांकि अभी मेकर्स ने और फरहान ने इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया। बता दें वह इस प्रोजेक्ट से निर्माता के तौर पर भी जुड़े हुए हैं। क्रिकेटर लाला अमरनाथ पर बन रही इस बायोपिक को कई निर्माता मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसमें फरहान समेत आशुतोष गोवारिकर और आमिर खान का नाम भी शामिल है। 2001 में रिलीज हुई फिल्म लगान के बाद से आशुतोष और आमिर ने कोई फिल्म साथ में नहीं की। मगर इस आगामी प्रोजेक्ट से दोनों एक बार फिर साथ काम करते दिख सकते हैं। यह स्पोर्ट्स-ड्रामा फिल्म क्रिकेट और भारत-पाकिस्तान के विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित होगी। चर्चा है कि फिल्म में आमिर खान खुद स्वतंत्र भारत के पहले कप्तान लाला अमरनाथ का किरदार निभाते नजर आएंगे। इस फिल्म की कहानी राजकुमार हिरानी और अभिजात जोशी ने मिलकर लिखी है। फिल्म की शूटिंग अक्टूबर 2026 के आसपास शुरू होने की संभावना है।

करिश्मा कपूर आखिरी बार 2024 में मर्डर मुबारक में नजर आई थीं। एक समय अपने रोमांटिक किरदारों के लिए जानी जाने वाली एक्ट्रेस अब ब्राउन में नजर आने वाली हैं। इस वेब सीरीज का टीजर भी रिलीज हो चुका है, जिसे देखकर अभिनेत्री के फैंस बेहद खुश हैं।

वेब सीरीज ब्राउन में करिश्मा कपूर पुलिस अधिकारी के रूप में नजर आएंगी। टीजर के मुताबिक वह रीटा ब्राउन का किरदार निभाएंगी, जो एक ईमानदार पुलिस अधिकारी है। इसके साथ ही वह एक बहुत ही गंभीर केस की जांच कर रही है। अपने व्यक्तिगत जीवन में वह कई समस्याओं से जूझ रही है। मगर वह अपने फर्ज को शिद्दत से निभाती है।

वेब सीरीज ब्राउन की कहानी मुख्य रूप से उपन्यास सिटी ऑफ डेथ पर आधारित है, जिसे 2016 में अभिनेता ने लिखा था। सीरीज

पुलिसिया अंदाज में करिश्मा कपूर ने वेबसीरीज 'ब्राउन' से की वापसी



का मुख्य किरदार रीता ब्राउन एक

तेजतरार पुलिस अधिकारी है, जो अपने आस-पास की दुनिया से ऊब चुकी है। इसके साथ ही वह शराब की लत से जूझ रही है। यह सीरीज टीजर देखने पर किसी साइकोलॉजिकल थ्रिलर ड्रामा जैसी लग रही है।

वेब सीरीज ब्राउन से सिर्फ करिश्मा ही नहीं, बल्कि हेलेन भी अभिनय की दुनिया में वापसी कर रही हैं। इसके साथ ही सीरीज में सोनी राजदान, सूर्या शर्मा और के. के. रैना भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। हालांकि वेब सीरीज की रिलीज डेट की कोई आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं हुई है।

'मां इंटी बंगारम' का ट्रेलर रिलीज एक्शन मोड में नजर आयीं सामंथा

सामंथा रूथ प्रभु की बहुप्रतीक्षित एक्शन फिल्म मां इंटी बंगारम का ट्रेलर आखिरकार तौर पर रिलीज हो गया है। ट्रेलर में सामंथा को पहले से बिल्कुल अलग और एक्शन स्टाइल में देखा जा सकता है। ट्रेलर को लेकर सोशल मीडिया पर यूजर्स अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

ट्रेलर की शुरुआत में सामंथा एक अच्छी बहू बनने की कोशिश करती दिखाई देती हैं। परिवार की उम्मीदों को पूरा करने में उन्हें काफी मुश्किलें आती हैं। लेकिन अचानक कहानी में ट्विस्ट आता है और सामंथा अपने परिवार की रक्षा के लिए खतरनाक दुश्मनों से लड़ती नजर आती हैं। ट्रेलर में उनके एक्शन

सीन्स बहुत दमदार हैं। सामंथा की फिल्म मां इंटी बंगारम पहले 15 मई को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब इसे टाल दिया गया है। फिल्म मां इंटी बंगारम 19 जून 2026 को

बॉलीवुड

मसाला

सिनेमाघरों में रिलीज होगी। सामंथा ने इंस्टाग्राम पर ट्रेलर जारी किया और लिखा, अब ट्रिगर दबाने का समय आ गया है। फिल्म के निर्देशक नंदिनी रेड्डी हैं। इसे राज, सामंथा रूथ प्रभु और हिमांक ने मिलकर बनाया है। फिल्म मां इंटी



बंगारम एक ऐसी महिला की कहानी है, जो पारंपरिक परिवार में नई बहू बनकर आती है।

वह शांत, आज्ञाकारी और सबकी नजर में रहने वाली लगती है। लेकिन परिवार को यह पता नहीं होता कि उसके अंदर क्या राज छिपा है। जब

उसका पुराना अतीत वापस लौटता है, तो उसे अपने परिवार की रक्षा करनी पड़ती है, वो भी बिना अपनी असली पहचान बताए।

अजब-गजब

इतिहास का सबसे जबरदस्त विस्फोट

यह विस्फोट सुनते ही बहरे हो गए थे लोग, फट गए थे कान के परदे!

निया में एक बार फिर से न्यूक्लियर विस्फोट के कयास लगाए जा रहे हैं। इस विस्फोट से होने वाले नुकसान के अलावा इसके आवाज की भी चर्चा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतिहास का सबसे जबरदस्त विस्फोट कब हुआ था? ये किसी मानव रचित यंत्र से नहीं, बल्कि एक ज्वालामुखी के विस्फोट से हुआ था, जिसकी वजह से कई लोग बहरे हो गए थे।

27 अगस्त 1883 का दिन दुनिया के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। इंडोनेशिया के सुंडा जलडमरु में स्थित क्राकाटोआ द्वीप पर स्थित ज्वालामुखी ने उस दिन ऐसा विस्फोट किया जिसकी आवाज आज तक किसी भी मानव निर्मित हथियार या विस्फोट से ज्यादा तेज साबित हुई। वैज्ञानिकों के अनुसार इस विस्फोट की तीव्रता 310 डेसिबल तक पहुंच गई थी, जो ध्वनि की भौतिक सीमा से भी आगे थी।

जब क्राकाटोआ फटा तो आसमान में राख का ऐसा गुबार उठा कि दिन में भी रात हो गई। विस्फोट की ध्वनि ने आसपास के इलाकों में भारी तबाही मचाई। 40 मील दूर तक खड़े नाविकों के कान के परदे फट गए। कई लोग स्थायी रूप से बहरे हो गए। ध्वनि की लहर इतनी शक्तिशाली थी कि वह एक सुपरसोनिक शॉकवेव में बदल गई।

सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि क्राकाटोआ की आवाज 3000 मील दूर रोज़र्स द्वीप (भारतीय महासागर) तक सुनाई दी थी। वहां



के लोगों ने इसे भारी तोपों की गोलाबारी जैसी आवाज बताया था। कल्पना कीजिए, न्यूयॉर्क में बैठे व्यक्ति को डबलिन की आवाज साफ सुनाई दे रही हो। यही हाल क्राकाटोआ का था। इस ध्वनि तरंग ने पूरे पृथ्वी के वायुमंडल में 7 बार चक्कर लगाए। पांच दिनों तक यह आवाज गूंजती रही थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि इतिहास में दर्ज किसी भी विस्फोट की आवाज इससे ज्यादा तेज नहीं थी। यहां तक कि परमाणु बम के परीक्षण भी इसकी तुलना में कमजोर साबित होते हैं।

विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि पूरा क्राकाटोआ द्वीप लगभग नष्ट हो गया। 36,000 से ज्यादा लोग मारे गए, ज्यादातर सुनामी की वजह से। 30 मीटर ऊंची लहरें उठीं जिन्होंने तटीय

इलाकों को तबाह कर दिया था। राख का गुबार 80 किलोमीटर ऊपर तक पहुंच गया, जिससे विश्व स्तर पर मौसम प्रभावित हुआ। कई महीनों तक सूर्यास्त लाल और भयावह दिखाई देते थे। क्राकाटोआ विस्फोट ने वैज्ञानिकों को बहुत कुछ सिखाया। इस घटना ने प्लेट टैक्टॉनिक्स और ज्वालामुखी विज्ञान की समझ को नई दिशा दी। आज भी क्राकाटोआ क्षेत्र सक्रिय है और क्राकाटोआ का बच्चा नामक नया ज्वालामुखी उभरा हुआ है, जो भविष्य में फिर से खतरनाक साबित हो सकता है। उस समय के समाचार पत्रों में इस घटना को दुनिया का अंत जैसा बताया गया था। नाविकों ने अपनी डायरियों में लिखा कि ऐसा लगा जैसे पृथ्वी चीख रही हो।

इसे कहा जाता है दुनिया का इकलौता तैरता हुआ नेशनल पार्क, किसी जन्त से कम नहीं!

भारत अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और अनोखी जगहों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। कहीं बर्फ से ढके पहाड़ हैं, कहीं घने जंगल और कहीं शांत झीलें। लेकिन इन सबके बीच पूर्वोत्तर भारत के Manipur में मौजूद एक ऐसी जगह भी है, जिसे



देखकर पहली बार में यकीन करना मुश्किल हो जाता है। यहां जंगल जमीन पर नहीं, बल्कि पानी के ऊपर तैरता हुआ दिखाई देता है। यही वजह है कि Keibul Lamjao National Park को दुनिया का इकलौता तैरता हुआ नेशनल पार्क कहा जाता है। यह अनोखा नेशनल पार्क मणिपुर की राजधानी इम्फाल से लगभग 53 किलोमीटर दूर स्थित है। यह मशहूर Loktak Lake के ऊपर फैला हुआ है और करीब 40 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में मौजूद है। यहां पहुंचते ही ऐसा महसूस होता है जैसे प्रकृति ने पानी और जंगल को एक साथ मिलाकर कोई जादुई दुनिया बना दी हो। चारों तरफ फैला शांत पानी, हरियाली और तैरते हुए छोटे-छोटे भूभाग इस जगह को बेहद खास बनाते हैं। इस पार्क की सबसे बड़ी खासियत यहां मौजूद फुमडी हैं। फुमडी दरअसल मिट्टी, घास, पेड़-पौधों और दूसरे जैविक पदार्थों से मिलकर बने प्राकृतिक तैरते हुए द्वीप होते हैं। ये मौसम के हिसाब से अपना रूप बदलते रहते हैं। बारिश के समय जब झील का जलस्तर बढ़ जाता है, तब ये पानी के ऊपर तैरने लगते हैं। वहीं सर्दियों में नीचे बैठकर झील की सतह से पोषण लेते हैं। यही कारण है कि यहां चलते समय कई बार ऐसा एहसास होता है जैसे जमीन खुद पानी पर तैर रही हो। यह पार्क सिर्फ अपने तैरते जंगल की वजह से ही नहीं, बल्कि दुर्लभ संगई हिरण के कारण भी प्रसिद्ध है। Sangai को मणिपुर का राज्य पशु माना जाता है। इसकी चाल इतनी खास होती है कि जब यह फुमडी पर चलता है, तो ऐसा लगता है जैसे कोई नर्तक मंच पर प्रस्तुति दे रहा हो। इसी वजह से इसे डांसिंग डिग्जर भी कहा जाता है। वन्यजीव प्रेमियों और फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए यह जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं मानी जाती। यहां आने वाले पर्यटक डोंगी की सवारी का भी आनंद लेते हैं। पानी के बीच तैरते द्वीपों और घास से घिरे रास्तों से गुजरना किसी फिल्मी दृश्य जैसा अनुभव देता है। खासकर सुबह के समय यहां का नजारा बेहद शांत और मनमोहक दिखाई देता है।

महाराष्ट्र एमएलसी चुनावों को लेकर घमासान

बीजेपी, शिंदे गुट की शिवसेना और एनसीपी के बीच विवाद

» छत्रपति संभाजीनगर नासिक और पुणे सीटों पर महायुति में रार

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

मुंबई। महाराष्ट्र एमएलसी चुनावों को लेकर फिर घामसान मचा है। सत्तारूढ़ महायुति का सीट बंटवारा फंसा हुआ है, जहाँ 17 में से तीन अहम सीटें - नासिक, छत्रपति संभाजीनगर और पुणे - बीजेपी, शिंदे गुट की शिवसेना और एनसीपी के बीच विवाद की वजह बन गई है। इनको लेकर तीनों दलों के बीच रार मच गया है। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना नासिक और संभाजीनगर पर पारंपरिक गढ़ होने का दावा कर रही है, जबकि एनसीपी पुणे पर जोर दे रही है, वहीं भाजपा तीनों सीटों पर अपना हक जता रही है। इस खींचतान के बीच मौजूदा 12:3:2 के फॉर्मूले पर भी शिवसेना की आपत्ति ने सियासी पेंच और उलझा दिया है।

महायुति ने स्थानीय निकायों के द्विवार्षिक एमएलसी चुनावों के लिए

बातचीत के जरिए विवादों का समाधान करेंगे : फडणवीस

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महायुति के सहयोगी दल बातचीत के जरिए विवादों का समाधान करेंगे। उन्होंने बताया कि नासिक और संभाजीनगर सीटों को लेकर शिवसेना से और पुणे सीट को लेकर एनसीपी से बातचीत चल रही है। फडणवीस ने कहा कि नासिक, संभाजीनगर और पुणे - इन तीन विवादित सीटों को लेकर मतभेद अभी भी बना हुआ है, जिसे सुलझाना बाकी है। शिवसेना नेताओं का तर्क है कि नासिक और संभाजीनगर पार्टी के पारंपरिक गढ़ हैं और उन्होंने वहाँ सीटों पर जीत का भारोसा जताया है।

12:3:2 का फॉर्मूला तय कर लिया है। हालांकि, 17 सीटों में से तीन सीटें - नासिक,



शिवसेना-भाजपा की बातचीत बेनतीजा

इससे पहले, भाजपा के वरिष्ठ नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए एकनाथ शिंदे से मुलाकात की थी, लेकिन बातचीत बेनतीजा रही। चुनाव आयोग ने एमएलसी (स्थानीय निकाय) चुनावों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 1 जून है, मतदान 18 जून को होगा और मतगणना 22 जून को होगी। स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों के निर्वाचित सदस्य इन चुनावों में मतदान करने के पात्र होंगे।

छत्रपति संभाजीनगर और पुणे - गठबंधन के सहयोगी दलों के बीच विवाद का मुद्दा बनी हुई हैं। इन सीटों को लेकर भाजपा, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बीच खींचतान शुरू हो गई है। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली

पुणे में मेरे पास स्थानीय निकाय प्रतिनिधियों की सबसे बड़ी संख्या : एनसीपी

दूसरी ओर, एनसीपी का कहना है कि पुणे में उसके पास स्थानीय निकाय प्रतिनिधियों की सबसे बड़ी संख्या है, जिससे वह इस निर्वाचन क्षेत्र में स्वाभाविक दावेदार बन जाती है। शिवसेना ने भाजपा, शिवसेना और एनसीपी के बीच मौजूदा 12:3:2 के सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर भी आपत्ति जताई है। पार्टी नेता कथित तौर पर तीन के बजाय चार सीटें मांग रहे हैं। अगर शिवसेना की मांग मान ली जाती है, तो एनसीपी को सिर्फ एक सीट से ही संतोष करना पड़ सकता है, जिससे संगठित रूप से सीट बंटवारे का फॉर्मूला 12:4:1 हो जाएगा।

शिवसेना ने नासिक और संभाजीनगर सीटों पर दावा जताया है, जबकि एनसीपी पुणे सीट पर जोर लगा रही है। वहीं, भाजपा ने तीनों सीटों पर अपना दावा पेश किया है।

लद्दाख के एलजी की सोनम वांगचुक को सख्त चेतावनी

» कहा- गुमराह करने वाले और भड़काऊ नैरेटिव से माहौल खराब न करें

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। लद्दाख के उपराज्यपाल (एलजी) विनय कुमार सक्सेना ने मंगलवार (26 मई 26) को राजभवन में प्रसिद्ध जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक और उनकी पत्नी गीतांजलि अंगमो से एक अहम मुलाकात की। यह मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ हुई हालिया रचनात्मक बातचीत के ठीक बाद हुई है।



हालांकि, इस खुली बातचीत के दौरान उपराज्यपाल ने वांगचुक को क्षेत्र में गुमराह करने वाला नैरेटिव फैलाने और सार्वजनिक चर्चा का माहौल खराब करने के खिलाफ सख्त लहजे में चेताया है। सक्सेना ने जोर देकर कहा कि लद्दाख में राजनीतिक बातचीत और चल रही विकास योजनाओं, दोनों के संबंध में सकारात्मक माहौल बनाए रखना बेहद जरूरी है। उपराज्यपाल ने कहा कि मुलाकात के दौरान कार्यकर्ता और उनकी पत्नी के साथ उनकी खुली बातचीत हुई। उन्होंने लद्दाख में राजनीतिक बातचीत और चल रही विकास पहलों, दोनों के संबंध में सकारात्मक माहौल बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। सक्सेना के अनुसार, वांगचुक ने स्वीकार किया कि लद्दाख की स्थिति की तुलना मणिपुर की स्थिति से करना निर्णय लेने में हुई एक गलती थी। उन्होंने स्वीकार किया कि लद्दाख की स्थिति की तुलना मणिपुर से करना निर्णय लेने में हुई एक गलती थी।

करो या मरो के मैच में उतरेंगे हैदराबाद और राजस्थान

» हैदराबाद का प्लेऑफ में खराब रहा है रिकार्ड

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

मुल्तापुर। आईपीएल 2026 के एलिमिनेटर मुकाबले में बुधवार को यानी आज सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) की भिड़ंत राजस्थान रॉयल्स (आरआर) के साथ होगी। दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला मुल्तापुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। हैदराबाद ग्रुप चरण में तीसरे स्थान पर रहा था, जबकि राजस्थान की टीम चौथे स्थान पर रहकर प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम बनी थी।

सनराइजर्स हैदराबाद का रिकार्ड आईपीएल प्लेऑफ में खराब रहा है।

एसआरएच आठवीं बार अंतिम चार में पहुंची है। टीम ने प्लेऑफ में अब तक कुल 14 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से सनराइजर्स हैदराबाद को



खिताब का बचाव करने से एक कदम दूर आरसीबी

धर्मशाला। गत चैपियन आरसीबी की टीम गुजरात टाइटंस को 92 रनों से हराकर लगातार दूसरी बार आईपीएल के फाइनल में पहुंच गई है। आरसीबी ने कप्तान रजत पाटीदार की विस्फोटक पारी से 20 ओवर में पांच विकेट पर 254 रन बनाए। जबकि गुजरात की टीम 19.3 ओवर में 162 रन पर ऑलआउट हो गई। गुजरात के पास हालांकि, अभी भी फाइनल में जाने का एक मौका है। टीम अब हैदराबाद और राजस्थान के बीच बुधवार को होने वाले एलिमिनेटर की विजेता टीम से शुक्रवार को क्वालिफायर-2 में भिड़ेगी। आरसीबी ने इस तरह कुल पांचवीं बार आईपीएल के फाइनल में जगह बनाई है। टीम इससे पहले, 2009, 2011, 2016 और 2025 में फाइनल में पहुंची थी। टीम ने पिछले सीजन पंजाब किंग्स को हराकर खिताब अपने नाम किया था और टीम खिताब का बचाव करने से एक कदम दूर है। दूसरी ओर, गुजरात के लिए एस जैय में कुछ अच्छा नहीं रहा। टीम के गेंदबाज जहां महंजो साबित हुए, वहीं बल्लेबाजों परी तरह पराजित रही। इमरतव प्लेयर के तौर पर उठे रहलु तेवतिया ने भले ही अर्धशतक लगाया, लेकिन टीम का अन्य कोई बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल सका।

एआईएडीएमके के 3 विधायकों का इस्तीफा

» सभी विधायक टीवीके पार्टी में हुए शामिल

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

चेन्नई। एआईएडीएमके को एक और झटका लगा है। आईएडीएमके के तीन विधायकों ने तमिलनाडु विधानसभा से इस्तीफा दे दिया और मुख्यमंत्री विजय के नेतृत्व वाली टीवीके पार्टी में शामिल हो गए। विधायकों मरगथम कुमारवेल, जयकुमार और सत्यबामा ने तमिलनाडु विधानसभा अध्यक्ष जेसीडी प्रभाकर को अपना इस्तीफा सौंपा, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। यह घटनाक्रम एआईएडीएमके के वरिष्ठ नेता सीवी शनमुगम के नेतृत्व में 30 विधायकों द्वारा विजय की टीवीके सरकार को समर्थन देने के दो सप्ताह बाद सामने आया है। एडम्पाडी पलानीस्वामी के नेतृत्व वाली पार्टी से इस्तीफा देने वाले तीनों विधायक इसी बागी गुट का हिस्सा थे।

कुमारवेल ने मद्रुथकम निर्वाचन क्षेत्र से, सत्यबामा ने धारापुरम से और जयकुमार ने



पेरुंदुरई से एआईएडीएमके के टिकट पर जीत हासिल की थी। धारापुरम और पेरुंदुरई पश्चिमी तमिलनाडु के कोंगु क्षेत्र में अन्नाद्रमुक के पारंपरिक गढ़ का हिस्सा हैं, जबकि मद्रुथकम चेन्नई के पास स्थित है। अपना इस्तीफा सौंपने के तुरंत बाद, विधायकों ने टीवीके मंत्री आधव अर्जुन से उनके कक्ष में मुलाकात की। ये तीनों विधायक उन 25 विधायकों में शामिल थे जिन्होंने हाल ही में विजय के प्रति अपनी निष्ठा बदल ली और 13 मई को हुए फ्लोर टेस्ट में पार्टी व्हिप का

बंगाल में टीएमसी के 100 पार्षदों ने दिया त्याग पत्र

कभी शक्तिशाली रही ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तुणमूल कांग्रेस, बंगाल चुनावों में अपनी कसरी तर के बाद कमजोर पड़ती नजर आ रही है। लोकसभा सांसद काकोली घोष दस्तदार जैसे वरिष्ठ नेता खुलकर असंतोष व्यक्त कर रहे हैं, वहीं तुणमूल नियंत्रित नगर निकायों में अशांति के चलते सामूहिक इस्तीफे हो रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में विभिन्न नगरपालिकाओं के लगभग 100 पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया है। इस राजनीतिक उथल-पुथल ने भाजपा को उन नगर निकायों में अपनी पकड़ मजबूत करने का अवसर दिया है जो काफी हद तक तुणमूल के नियंत्रण में हैं। संकट इतना गंभीर हो गया है कि अगले साल होने वाले नगर निगम चुनावों से पहले ही कई नगर निगम बोर्डों को मंग किया जा सकता है।

उल्लंघन करते हुए टीवीके सरकार के समर्थन में मतदान किया। एआईएडीएमके के बागी विधायकों में से पांच ने पार्टी प्रमुख एडम्पाडी पलानीस्वामी के प्रति अपनी निष्ठा वापस लौटा ली है। इसके साथ ही विधानसभा में पलानीस्वामी का समर्थन करने वाले विधायकों की संख्या बढ़कर 27 हो गई है।

नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आसाराम की सजा बरकरार

जोधपुर कोर्ट ने कहा- सरेंडर करना होगा

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। राजस्थान हाई कोर्ट की जोधपुर बेंच ने बुधवार को नाबालिग छात्रा से यौन उत्पीड़न मामले में आसाराम को दोषी ठहराकर सजा बरकरार रखी। अदालत ने इस मामले में सह-आरोपी शिल्पी और शरतचंद्र को बरी कर दिया। आसाराम अंतरिम मेडिकल बेल पर जेल से बाहर हैं, लेकिन इस फैसले के बाद उन्हें सरेंडर करना होगा। आसाराम को अगस्त 2013 में जोधपुर स्थित आश्रम में एक नाबालिग छात्रा के यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। फिर 25 अप्रैल 2018 को विशेष पाँक्सो अदालत ने उन्हें दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी।

कलाकारों ने चित्रों से उंकेरी भावनाएं

» राज्य ललित कला अकादमी में पांच दिवसीय चित्रकला प्रदर्शनी अभिव्यक्ति प्रदर्शनी का समापन

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। राज्य ललित कला अकादमी, फैसरबाग, लखनऊ में आयोजित पांच दिवसीय चित्रकला प्रदर्शनी अभिव्यक्ति प्रदर्शनी का आज अत्यंत गरिमामय एवं भव्य समापन हुआ। प्रदर्शनी में शहर के लगभग 70 उभरते एवं प्रतिष्ठित कलाकारों की उत्कृष्ट कलाकृतियां प्रदर्शित की गईं, जिनमें सामाजिक सरोकार, प्रकृति, संस्कृति, मानवीय संवेदनाएं एवं समकालीन विषयों को आकर्षक रंगों और सशक्त अभिव्यक्तियों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। प्रदर्शनी में विभिन्न विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के 60 से अधिक युवा



कलाकारों की रचनात्मक पेंटिंग्स एवं कलात्मक प्रस्तुतियों ने कला प्रेमियों, बुद्धिजीवियों और दर्शकों को विशेष रूप से आकर्षित किया। प्रदर्शनी के दौरान कला दीर्घा में उत्साह, सृजनशीलता और सांस्कृतिक चेतना का अद्भुत वातावरण देखने को मिला। समापन समारोह के मुख्य अतिथि मनोज सिंह, पूर्व राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी एवं पूर्व कस्टम अधिकारी रहे।

राहुल गांधी दलितों को फिर से कांग्रेस के केंद्र में लाएंगे

जाति आधारित क्षेत्रीय दलों का उदय कांग्रेस की वजह से : नेता प्रतिपक्ष

4पीएम न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली। कांग्रेस एकबार फिर अपने को मजबूत करने में जुट गई है। केरल व तमिलनाडु में सरकार बनने के बाद जोश में आए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पार्टी के कीलकांटे फिर दुरुस्त करने की शुरुआत कर दी है। रायबरेली के सांसद यूपी विस चुनाव 27 से पहले कभी कांग्रेस के परंपरागत वोटर दलितों को फिर से अपनी ओर करने की कोशिश में जुट गए हैं।

दिल्ली में एक कार्यक्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि दलित अब पार्टी के भीतर एक केंद्रीय भूमिका निभाएंगे, और उन्होंने जाति आधारित क्षेत्रीय दलों के उदय का श्रेय पिछले दशकों में कांग्रेस की अपनी नीतियों को दिया। 26 जनवरी को कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी के अनुसूचित जाति विभाग की बैठक को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि अगर कांग्रेस ने 1980 और 90 के दशक के दौरान दलितों के लिए उचित उपाय किए होते, तो न तो जाति आधारित क्षेत्रीय पार्टियां उभरतीं और न ही दलित उनकी ओर आकर्षित होते।

ठीक एक साल पहले, राहुल गांधी ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया था कि कांग्रेस ने ओबीसी समुदाय की उपेक्षा की है और इसके लिए माफी मांगी थी। अब उन्होंने दलित समुदाय के बारे में भी इसी तरह की भावना व्यक्त की है। इन प्रयासों के माध्यम से राहुल गांधी दलित और

यूपी विस चुनाव पर नजर

इस रणनीति ने दलित मतदाताओं के बीच कांग्रेस और इडिया गठबंधन को चुनावी लाभ दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राहुल गांधी ने ओबीसी श्रेणी के लिए जाति जनगणना की भी वकालत की है। इन सभी पहलों के चलते लोकसभा में कांग्रेस पार्टी की सीटों की संख्या दोगुनी हो गई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही राहुल गांधी दलित और पिछड़े वर्गों तक अपनी पहुंच बढ़ाने के प्रयास तेज कर रहे हैं। पिछले सप्ताह उन्होंने अपने रायबरेली निर्वाचन क्षेत्र में दलित स्वतंत्रता सेनानी वीर पासी की प्रतिमा का अनावरण किया और एक बहुजन सभा को संबोधित किया।

बसपा संस्थापक कांशीराम की प्रशंसा की

बैठक में मौजूद सूत्रों के अनुसार, राहुल गांधी ने दलित समुदाय को एकजुट करने और उनमें आत्मविश्वास जगाने के लिए बसपा संस्थापक कांशीराम की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि भाजपा एक साथ क्षेत्रीय दलों को मंग कर देने और दलितों के अधिकारों को छीनने का प्रयास कर रही है, जिससे दलितों के खिलाफ अत्याचार बढ़ रहे हैं। राहुल गांधी ने इस बात पर जोर दिया कि कांग्रेस दलित अधिकारों की रक्षा करेगी और बाबासाहेब अंबेडकर के सपनों को साकार करेगी, साथ ही उन्होंने कहा कि दलित पार्टी में अहम भूमिका निभाएंगे।

पिछड़े समुदायों के बीच कांग्रेस की स्थिति को प्रदर्शित करते हुए रैलियां निकालीं और आरोप मजबूत करते नजर आ रहे हैं। हाल ही में हुए लगाया कि मोदी सरकार के कार्यकाल में संविधान लोकसभा चुनावों के दौरान उन्होंने संविधान खतरे में है।

पुण्यतिथि पर याद किए गए पं. नेहरू



4पीएम न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने देश के पहले प्रधानमंत्री और उनके पर-दादा पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर नेहरू को याद करते हुए लिखा, देश के प्रथम प्रधानमंत्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि।

आधुनिक भारत की मजबूत नींव रखते हुए उन्होंने एक समावेशी, सौहार्दपूर्ण और प्रगतिशील भारत निर्माण के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया। इसके साथ राहुल गांधी ने शांति वन पहुंचकर श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए कई तस्वीरें भी साझा कीं, जिनमें वह मौन श्रद्धांजलि देते नजर आए। साथ ही, उनके साथ कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे भी नजर आए। राहुल गांधी ने अपने संदेश में नेहरू के उस विजन को भी रेखांकित किया, जिसमें स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक मूल्यों, संवैधानिक अधिकारों, सामाजिक न्याय और वैज्ञानिक सोच को भारत की आत्मा बताया गया था। कांग्रेस लगातार यह संदेश देती रही है कि नेहरू ने केवल राजनीतिक आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी, बल्कि स्वतंत्र भारत के संस्थाओं, लोकतांत्रिक ढांचे और आधुनिक विकास मॉडल की भी बुनियाद रखी। नेहरू की पुण्यतिथि पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने भी शांति वन पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पर उन्हें याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की।

स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव बहुत जरूरी: सुप्रीम कोर्ट

शीर्ष अदालत ने एसआईआर की वैधता को बरकरार रखा

4पीएम न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली। बुधवार को सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) द्वारा किए गए मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की वैधता को बरकरार रखते हुए कहा कि यह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यता को आगे बढ़ाता है। न्यायालय ने कहा कि एसआईआर का संचालन निर्वाचन आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है।

भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) सुर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने व्यवस्था दी कि यह नहीं कहा जा सकता कि निर्वाचन आयोग ने एसआईआर का प्रयोग करके अपने वैधानिक अधिकारों की सीमा से बाहर जाकर काम किया है। पीठ ने कहा कि हम इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते कि विवादित प्रक्रिया केवल प्रशासनिक सुविधा के लिए अपनाई गई थी। इसके विपरीत, हम मानते हैं कि

चुनावी एसआईआर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की संवैधानिक आवश्यकता को बल देता है। एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं में दावा किया गया था कि संविधान के अनुच्छेद 326, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और उससे संबंधित नियमों के तहत निर्वाचन आयोग को इतने व्यापक स्तर पर एसआईआर कराने का अधिकार नहीं है।

शीर्ष न्यायालय ने 29 जनवरी को इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। इन याचिकाओं में गैर-सरकारी संगठन 'एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्मर्स' (एडीआर) की याचिका भी शामिल थी। बिहार में एसआईआर अभियान का पहला चरण चलाया गया था। पिछले वर्ष 12 अगस्त को न्यायालय ने मामले में अंतिम बहस शुरू की थी और तब कहा था कि मतदाता सूची में नाम शामिल करना या हटाना निर्वाचन आयोग के संवैधानिक अधिकार क्षेत्र में आता है। निर्वाचन आयोग ने एसआईआर अभियान के तहत प्रकाशित मसौदा मतदाता सूची से हटाए गए 65 लाख लोगों के नाम सार्वजनिक किए थे। एसआईआर अधिसूचना के अनुसार, जिन मतदाताओं के नाम 2002 या 2003 की मतदाता सूची में नहीं थे, उन्हें उस समय सूची में शामिल किसी व्यक्ति से अपना पैतृक संबंध साबित करना था।

टीएमसी के 50 विधायक व 20 सांसद भाजपा के संपर्क में: सौमित्र खान

4पीएम न्यूज नेटवर्क

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर बड़ा भूचाल आने के संकेत मिल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के सांसद सौमित्र खान ने बुधवार को एक सनसनीखेज दावा करते हुए कहा कि ममता बनर्जी की अगुवाई वाली सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के लगभग 50 विधायक और 20 सांसद पार्टी नेतृत्व से बेहद नाखुश हैं।

खान के मुताबिक, यदि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व हरी झंडी दे देता है, तो ये सभी नेता तृणमूल छोड़कर भाजपा में शामिल होने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

पूर्व सीएम पिनराई विजयन के आवास पर ईडी की छापेमारी

सीएमआरएल मामले में 10 ठिकानों पर तलाशी

4पीएम न्यूज नेटवर्क

तिरुवंतनपुरम। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कोचीन मिनरल्स एंड रुटाइल लिमिटेड (सीएमआरएल) से जुड़े कथित धनशोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) मामले में बड़ी कार्रवाई की है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने बुधवार को केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और अन्य संबंधित लोगों के ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की।

अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार, यह कार्रवाई धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत की जा रही है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

पेपर लीक मामले में सीबीआई का एक्शन लातूर के डॉक्टर और पुणे के कोचिंग टीचर समेत 2 और गिरफ्तार

4पीएम न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली। मेडिकल प्रवेश परीक्षा 26 के कथित पेपर लीक मामले की परतें जैसे-जैसे खुल रही हैं, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की कार्रवाई तेज होती जा रही है। बुधवार (27 मई 2026) को सीबीआई ने इस हाई-प्रोफाइल मामले में एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए दो और मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

अधिकारियों के मुताबिक, गिरफ्तार किए गए लोगों में लातूर का एक डॉक्टर और पुणे के एक प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान का फिजिक्स टीचर शामिल है। इन दो नई गिरफ्तारियों के साथ ही हथशुद्ध त पेपर लीक घोटाले में अब तक सलाखों के पीछे पहुंचने वाले आरोपियों की कुल संख्या बढ़कर 13 हो गई है। जांच



एजेंसी ने लातूर के डॉक्टर, डॉ. मनोज शिरुरे को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने बताया कि शिरुरे पर आरोप है कि उन्होंने रेणुकाई करियर सेंटर के संस्थापक शिवराज मोटेगाँवकर के बेटे सहित तीन छात्रों को, आरोपी कुलकर्णी से केमिस्ट्री के सवाल दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। अधिकारियों ने बताया कि एजेंसी ने पुणे स्थित कोचिंग सेंटर, डॉ. अभंग प्रभु मेडिकल एकेडमी में फिजिक्स के टीचर, तेजस हर्षदकुमार शाह को भी गिरफ्तार किया है। शाह पर आरोप है कि उसने गिरफ्तार आरोपी मनीषा हवलदार से फिजिक्स के लीक हुए सवाल हासिल किए थे।



अधिकारियों ने बताया कि धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत राज्य में कुल 10 परिसरों पर तलाशी ली जा रही है, जिनमें राजधानी तिरुवंतनपुरम स्थित विजयन का किराए का मकान भी शामिल है। आरोप है कि निजी कंपनी कोचीन मिनरल्स एंड रुटाइल लिमिटेड ने 18 से 19 के बीच विजयन की बेटी टी. वीणा की कंपनी एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस को 1.72 करोड़ रुपये का अवैध भुगतान किया, जबकि इस आईटी कंपनी ने सीएमआरएल को कोई सेवा प्रदान नहीं की थी। ईडी की यह छापेमारी केरल

उच्च न्यायालय द्वारा सीएमआरएल को बड़ा झटका दिए जाने के ठीक अगले दिन हुई है। मंगलवार को ही उच्च न्यायालय ने सीएमआरएल को उस याचिका को सिरे से खारिज कर दिया था, जिसमें कंपनी ने ईडी द्वारा की जा रही कानूनी कार्रवाई को रद्द करने का अनुरोध किया था। कोर्ट से हरी झंडी मिलते ही ईडी ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी। उल्लेखनीय है कि इस कथित वित्तीय अनियमितता और अवैध लेनदेन के आरोपों की गंभीरता को देखते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने साल 024 में पीएमएलए के तहत औपचारिक मामला दर्ज कर अपनी जांच शुरू की थी। इसी जांच के तहत अब साक्ष्य जुटाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री और उनसे जुड़े अन्य लोगों के ठिकानों पर यह छापेमारी की गई है।